



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 80]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 25, 2003/चैत्र 4, 1925

No. 80]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 25, 2003/CHAITRA 4, 1925

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी तथा संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2003

मध्यावधि समीक्षा का प्रारंभीकरण

विषय : चीन जनवादी गणराज्य से फ्यूज्ड मैग्नेशिया पर लगाये गये पाटनरोधी शुल्क के बारे में मध्यावधि समीक्षा का प्रारंभीकरण।

सं. 18/1/1997-डीजीएडी.—नामित प्राधिकारी (जिन्हें इनके बाद प्राधिकारी कहा गया है), सीमा शुल्क टैरिफ (पाटी गई वस्तु की पहचान, उस पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन तथा संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियम, 1995 (1995 की संख्या 6) द्वारा यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 की संख्या 51) के अनुसार चीन जनवादी गणराज्य मूल के अथवा वहां से निर्यातित फ्यूज्ड मैग्नेशिया (यथा उल्लिखित) के आयात पर निर्णायक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं। अंतिम शुल्क लगाये जाने की सिफारिश दिनांक 2-2-1999 के राजपत्र संख्या 18/1/97 ए0डी0डी द्वारा की गई थी, जिसे दिनांक 17-3-1999 की कस्टम्स अधिसूचना संख्या 35/99 कस्टम द्वारा लगाया गया था।

शामिल उत्पाद:

मौजूदा अल्पावधि समीक्षा में विचाराधीन उत्पादन- फ्यूज्ड मैग्नेशिया है ।

फ्यूज्ड मैग्नेशिया एक ऐसा मैग्नेशिया है जिसका प्रयोग मुख्यातया इस्पात उत्पादन में रिफ्रैक्टरी सामग्री के रूप में किया जाता है । मैग्नेशिया, प्राकृतिक स्रोतों (अर्थात् फ्यूज्ड मैग्नेशिया) तथा सिंथेटिक स्रोतों (अर्थात् समुद्री जल मैग्नेशिया) से प्राप्त होता है । इस दोनों में से किसी भी स्रोत से प्राप्त मैग्नेशिया को सिंटेर्ड मैग्नेशिया (जैसे समुद्री जल मैग्नेशिया) प्राप्त करने के लिये सिंटेर्ड किया जा सकता है और फ्यूज्ड मैग्नेशिया प्राप्त करने के लिये फ्यूज्ड किया जा सकता है, फ्यूज्ड मैग्नेशिया का उत्पादन विभिन्न ग्रेडों में किया जाता है सामान्यतया इसे रासायनिक गुणों (जैसे mg O, CaO, SiO₂, Fe₂O₃, B₂O₃) तथा भौतिक गुणों (जैसे बल्क डेंसिटी, क्रिस्टल साइज, ड्राई पोरोसिटी) के रूप में वर्गीकृत किया गया है । विषयगत फ्यूज्ड मैग्नेशिया को फ्यूज्ड मैग्नेशिया के रूप में वर्णित किया है जिसको और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की अनुसूची 1 के सीमाशुल्क उप शीर्ष 2519.90 के अंतर्गत तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वर्गीकरण के 2519.90.01 और 2519.90.03 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है । तथापि, विनिर्माण, प्रक्रिया अथवा उसका प्रयोग तथा टैरिफ वर्गीकरण संकेतात्मक हैं और किसी भी प्रकार से मौजूदा जांच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है ।

2. प्रारंभीकरण:

सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम 1995 और सीमा शुल्क टैरिफ (पाटी गई वस्तु की पहचान, उस पर पाटनरोधी शुल्क का आंकलन तथा संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियम 1995 में यथाअधिसूचित नियम 23 के अनुसार प्राधिकारी के लिये यह अपेक्षित होता है कि वे पाटनरोधी शुल्क को बनाये रखने की आवश्यकता की समय समय पर समीक्षा करें ।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2000 की सिविल अपील संख्या 4936-4937 में अपने दिनांक 5-3-2000 के आदेश द्वारा प्राधिकारी को निदेश दिया है कि वह अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित का आंकलन करें-

- क. क्या बिरला पैरीक्लेज की फैक्ट्री फ्यूज्ड मैग्नेशिया के चीन के निर्यातकों द्वारा किये गये पाटन के परिणामस्वरूप बंद हुई थी अथवा नहीं और क्या यह फैक्ट्री जांच के बाद या इसके पहले बंद हुई थी ।
- ख. क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में पाटनरोधी शुल्क औचित्यपूर्ण बताया गया है ।
- ग. माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश की प्राप्ति के तीन महीनों के भीतर समीक्षा को पूरा करना ।

3 प्रक्रिया:

नामित प्राधिकारी, सीमा शुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम 1995 और सीमा शुल्क टैरिफ (पाटी गई वस्तु की पहचान, उस पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन तथा संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियम 1995 के अनुसार चीन जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित फ्यूज्ड मैग्नेशिया (यथाउल्लिखित) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने के लिये माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में एतद्वारा मध्यावधि समीक्षा शुरू करते हैं।

4. घरेलू उद्योग:

मैसर्स बिरला पैरीक्लेज, प्लॉट संख्या 1 किरलामपुडी लेआउट, बीच रोड विशाखापट्टनम-530017, आन्ध्रप्रदेश को पहले की अधिसूचनाओं में घरेलू उद्योग माना गया था । प्राधिकारी, उपर्युक्त नियमों के अनुसार इस कंपनी को घरेलू उद्योग मानने का प्रस्ताव करते हैं ।

5. जांच की अवधि:

इस मामले में जांच की अवधि 1-1-2002 से 31-12-2002 होगी ।

6. सूचना का प्रस्तुतीकरण:

संबद्ध देशों में निर्यातकों और भारत में संबंधित आयातकों और घरेलू उद्योग को अलग से पत्र लिखे जा रहे हैं कि वे अपने विचारों से अवगत कराने के लिये निर्धारित फार्म में और निर्धारित ढंग से संबंधित सूचना निम्नलिखित को प्रस्तुत करें -

नामित प्राधिकारी
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
पाटनरोधी और सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय
उद्योग भवन, नई दिल्ली - 110011

कोई अन्य हितबद्ध पक्ष भी निर्धारित फार्म और पद्धति में नीचे दी गई समय सीमा के भीतर जांच से संबंधित संगत निवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

7. समय सीमा:

मौजूदा अल्पावधि समीक्षा से संबंधित कोई भी सूचना लिखित रूप में भेजी जानी चाहिए और यह इस समीक्षा अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर उल्लिखित पते पर प्राधिकारी को पहुंच जानी चाहिए।

8. लोक सुनवाई:

माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्राधिकारी को निदेश दिया है कि वह तीन महीनों के भीतर अर्थात् 11.6.2003 तक समीक्षा को पूरा करें। अतः निर्धारित समय सीमा के भीतर समीक्षा पूरा करने के लिए, प्रारंभीकरण नोटिस के साथ ही लोक सुनवाई के लिए नोटिस भी दिया जा रहा है। प्राधिकारी सभी हितबद्ध पक्षों को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देने और बाद में इन्हें लिखित रूप में देने के लिए 30 अप्रैल 2003 को, कमरा सं० 141, उद्योग भवन, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में 3.00 बजे अपराह्न को लोक सुनवाई का आयोजन करेंगे।

9. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण:

नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पक्ष अन्य पक्षों द्वारा प्रस्तुत किये गये निवेदनों/साक्ष्य के अगोपनीय अंशों वाली सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है।

10. यदि कोई हितबद्ध पक्ष कोई सूचना देने से मना करता है अथवा एक उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना नहीं देता है अथवा जांच कार्य को महत्वपूर्ण रूप से बाधित करता है तो प्राधिकारी उनके अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्षों को रिकार्ड कर सकते हैं और केन्द्रीय सरकार को इस प्रकार की सिफारिशें कर सकते हैं जो वे ठीक समझें।

एल. वी. सप्तत्रयषि, नामित प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 2003

INITIATION (MID-TERM REVIEW)

Subject : Initiation of Mid-Term Review regarding anti-dumping duty imposed on Fused Magnesia from China PR.

No. 18/1/1997-DGAD.—The Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act 1975 (No.51 of 1975) as amended by Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 No.6 of 1995 read with Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 recommended (imposition of the definitive) Anti-Dumping duty on imports of Fused Magnesia (as mentioned above) originating in or exported from China PR. The final duty was recommended vide Gazette Notification No. 18/1/97/ADD dated 2.2.1999 which was imposed by Customs Notification No.35/99-Customs dated 17.3.1999.

Product Involved: The product under consideration in the present mid-term review is Fused Magnesia.

Fused Magnesia is a magnesia used as a refractory material primarily in steel production. Magnesia is available from natural sources (e.g. fused magnesia) as well as synthetic sources (e.g. sea water magnesia). Magnesia available from either of the two sources can be sintered to get sintered magnesia (like sea water magnesia) or fused to get fused magnesia. Fused magnesia is produced in various grades, generally classified in terms of its chemical properties (such as MgO, CaO, SiO₂, Al₂O₃, Fe₂O₃, B₂O₃) and physical properties (such as bulk density, crystal size, true porosity). The subject Fused Magnesia is classified under chapter custom sub-heading 2519.90 of Schedule 1 of the Customs Tariff Act, 1975 and under 2519.90.01 and 2519.90.03 of International Trade Classification. The classification is, however, indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.

2. Initiation: The Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 and the Rule 23 as Notified in Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of injury) Rules, 1995 made thereunder require the Authority to review from time to time, the need for continuance of Anti-Dumping duty.

The Hon'ble Supreme Court vide its Order dated 5.3.2003 in Civil Appeal No. 4936-4937 of 2000 has directed the Authority to assess the following inter-alia:

- a) Whether the closure of the factory of Birla Periclase (which was manufacturing sintered magnesia) was a result of the dumping carried out by Chinese exporters of Fused Magnesia or not and whether the closure was subsequent to the investigation or prior thereto
- b) Whether in the facts & circumstances of the case the continuation of the anti-dumping duty is justified.
- c) To complete the review within three months of receipt of the Hon'ble Supreme Court Order.

3. Procedure: The Designated Authority hereby initiates mid-term review in compliance with the directions of Hon'ble Supreme Court to review the need for continued imposition of the anti-dumping duty on imports of Fused Magnesia (as mentioned above) originating in or exported from China PR in accordance with the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995.

4. Domestic Industry: M/s.Birla Periclase, Plot No.1 Kirlampudi Layout, Beach Road, Vishakapatnam – 530 017, Andhra Pradesh was considered as the Domestic Industry in the earlier notifications. The Authority proposes to consider this company as the domestic industry in accordance with the Rules *supra*.

5. Period of Investigation: The period of investigation in this case will be from 1.1.2002 to 31.12.2002.

6. Submission of Information: The exporters in the subject countries and the importers in India known to be concerned and the domestic industry are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to :

The Designated Authority
Ministry of Commerce & Industry,
Department of Commerce,
Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties, Udyog Bhavan,
New Delhi – 110 011

Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

7. Time Limit: Any information relating to the present mid-term review should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than thirty days from the date of publication of this review notification.

8. Public Hearing: The Hon'ble Supreme Court has directed the authority to complete the review within three months i.e. by 11.06.2003. Therefore, the notice for Public Hearing is being given alongwith the initiation notice itself to complete the review within the stipulated time. The authority will hold Public Hearing on 30th April, 2003 in Room No. 141, Udyog Bhavan, Ministry of Commerce & Industry at 3.00 p.m. to provide an opportunity to all interested parties to express their views followed by written submissions

9. Inspection of Public File: In terms of Rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the submissions/evidence submitted by other interested parties.

10. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

L.V. SAPTHARISHI, Designated Authority